समतुल्य उद्यरण: ए० आई० आर० 1984 पैट 1323

पटना के उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

1979 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 149

निर्णय दिनांक: 09.07.1984

याचिकाकर्तागण: **योगेंद्र दास और अन्य**

बनाम

उत्तरदाता: **बिहार राज्य और अन्य**

भारत का संविधान- अनुच्छेद 311

कर्मचारियों का स्थांतरण एवं पदोन्नति

प्रश्न यह है कि ऐसे कर्मचारी जिन्हें उच्च प्रभाग क्लर्क के रूप में निम्न प्रभाग क्लर्क से पदोन्नति किया गया है, उनका वरीयता कैसे निश्चित किया जायेगा ।

यह मामला तीन सदस्यीय पीठ के पास निर्देशित किया गया ।

ट्रिसि नारायण झा बनाम बिहार राज्य; दिवानी रिट न्यायाधिकार 1099/1078 में प्रतिपादित निर्णय को पलट दिया गया तथा उमेश चन्द्र दास बनाम बिहार राज्य; दिवानी रिट न्यायाधिकार 1092/1973 को स्वीकृत किया गया ।

[पारा -8 तथा 9]

समतुल्य उद्यरण: ए० आई० आर० 1984 पैट 1323

पटना के उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

1979 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 149

निर्णय दिनांक: 09.07.1984

याचिकाकर्तागण: **योगेंद्र दास और अन्य**

बनाम

उत्तरदाता: **बिहार राज्य और अन्य**

माननीय न्यायाधीश कोरम:

एस.एस. संधवालिया, सी.जे., उदय सिन्हा और एस.एस. हसन, न्यायमूर्तिगण

वकीलगण:

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/वादी के लिए: राजेश्वर दयाल और राकेश्वर दयाल, अधिवक्तागण

उत्तरदाताओं के लिए: जे.पी. शुक्ला, सरकारी वकील सं. 02

निर्णय

एस.एस. संधवालिया, मुख्य न्यायाधीश

1. निम्न श्रेणी सहायकों को अन्य प्रभाग में पदोन्नति और उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए 24 अगस्त 1955 के वित्त विभाग के परिपत्र की व्याख्या से संबंधित मिसाल पर एक लंबे संघर्ष के कारण पूर्ण पीठ के लिए यह निर्देश आवश्यक हो गया है।

6 याचिकाकर्ताओं का दावा है कि राज्य सरकार के परिपत्र सं.जी/सी-1-1046/61-257 दिनांक (एस. आई. सी.) मार्च, 1961 6 के अनुसार खातों की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के परिणामस्वरूप उन्हें उच्च प्रभाग के रूप में पदोन्नत किया गया था। (अनुलग्नक '2')। ऐसा कहा जाता है कि याचिकाकर्ताओं की अस्थायी उच्च प्रभाग किरानी के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप, जो याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों से कनिष्ठ थे, उन्हें निचले पद (एस. आई. सी.) पर वापस कर दिया गया था। प्रत्यावर्तन से व्यथित, उक्त व्यक्तियों ने 1978 के 4125 और 1978 के 4351 सिविल रिट अधिकारिता मामलों को दायर दी थी, जिसमें इन याचिकाकर्ताओं को भी प्रतिवादी बनाया गया था। उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाओं में प्रत्यावर्तन पर रोक लगा दी, लेकिन यह रिट याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इससे किसी भी तरह से उच्च प्रभाग किरानी के रूप में उनकी पदोन्नति का आदेश प्रभावित नहीं हुआ। रिट याचिकाकर्ताओं की पीड़ा के लिए कहा जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने कथित रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन करते हुए रिट याचिकाकर्ताओं को लोअर डिवीजन किरानी के रूप में विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया था। याचिकाकर्ता प्रार्थना करते हैं कि उनके स्थानांतरण और निम्न वर्गीय क्लर्क को वापस करने के आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया जाए।

3. 25 जनवरी, 1979 को, प्रस्ताव पीठ ने इन रिट याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावर्तन और स्थानांतरण के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया और जब मामला 30 अप्रैल,

1984 को अंतिम सुनवाई के लिए आया, यह निर्देश दिया गया कि मामले को 1978 के सिविल रिट अधिकारिता मामले संख्या 4351 और 1978 के सिविल रिट अधिकारिता मामले संख्या 4125 के साथ एक बड़ी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाए, जिसमें निर्धारण के लिए समरूप प्रश्न उत्पन्न हुए थे। बाद के मामलों में, निदेश खंड पीठ ने सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 1092 में एक सीधा संघर्ष देखा। बिहार न्यायिक अकादमी 1973 (उमेश चंद्र दास बनाम बिहार राज्य) और सिविल रिट जर्नल। मामला सं. 1099 1978 (त्रिस नारायण झा बनाम बिहार राज्य), वित्त विभाग के विवादित परिपत्र की व्याख्या के संबंध में। इसे हल करने के लिए मामले को पूर्ण पीठ के पास भेजा गया था।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि सिविल रिट जर्नल 1978 की मामला सं. 4125 व्यतिक्रम के लिए खारिज किया गया। सिविल रिट जर्नल 4351/1978 में याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील ने कथित रिट आवेदन को वापस लेने के लिए प्रार्थना की, जिसे जाहिर तौर पर, समय बीतने के कारण और तदनुसार इसे वापसी के रूप में खारिज कर दिया गया। केवल वर्तमान रिट याचिका,की निर्णय के लिए बची हुई है।

5. दोनों पक्षों के विद्वान वकील हमारे सामने पूरी तरह से सहमत थे कि इस न्यायालय के समक्ष जो उमेश चंद्र दास (1973 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 3092) और त्रिदित नारायण झा (1978 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 1099) का मामला में अलग-अलग प्रतिपादित कानून ही मुद्दा है ।

6. अब यह सामान्य आधार है कि निचली स्तरीय सहायकों को ऊपरी प्रभाग में पदोन्नत करने का मामला और उनकी वरिष्ठता का मुद्दा किसी भी वैधानिक नियम द्वारा शासित नहीं है और इसका निर्धारण पूरी तरह से 24 अगस्त, 1955 के सरकारी परिपत्र के आधार पर किया जाना है। यह निम्नलिखित शब्दों में है:--

“अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति को ज्ञापांक संख्या 5 2-205/51-10551/-एफ का उल्लेख करने का निर्देश दिया जाता है और III-ई 2-2011/54-8326-एफ दिनांक 17 अक्टूबर, 1952 और 28 जुलाई, 1954, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि उच्च प्रभाग के पदों पर पर्याप्त पदोन्नति, जिसमें मेधावी निम्न प्रभाग सहायक, जिन्होंने उच्च प्रभाग परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, को मई, 1954 में आयोजित उच्च प्रभाग परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इस परीक्षा के परिणाम 30 सितंबर, 1954 को प्रकाशित किए गए थे। अब यह निर्णय लिया गया है कि स्थायी ऊपरी प्रभाग में रिक्तियों को अब से एक महत्वपूर्ण आधार पर भरा जा सकता है भले ही इसमें वरिष्ठ निचली प्रभागों सहायकों का स्थानापन्न होना शामिल हो, जिन्होंने उच्च श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो।

2. कुछ सहायक जो उच्च श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना उच्च प्रभाग में कार्य कर रहे थे उन्हें पिछली उच्च श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफलता के कारण निम्न श्रेणी में वापस जाना पड़ा। ऐसा सहायक उच्च प्रभाग में पदोन्नति के लिए पात्र होगा, यदि वह बाद में उच्च प्रभाग परीक्षा उत्तीर्ण करता है।

3. यदि उच्च प्रभाग में कोई रिक्ति है तो ऐसा सहायक, यदि वह अन्यथा पदोन्नति के लिए उपयुक्त है, तो इस रिक्ति के खिलाफ उच्च प्रभाग में पदोन्नत किया जाएगा। लेकिन, यदि कोई मौजूदा रिक्ति नहीं है और निम्न प्रभाग में उनका एक सहायक कनिष्ठ प्रभाग परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, पहले की तारीख से ही कार्य कर रहा है, तो सवाल उठता है कि क्या कनिष्ठ सहायक वरिष्ठ सहायक के लिए उच्च प्रभाग में एक रिक्ति को खाली करने के लिए निम्न प्रभाग में वापस जाने के लिए उत्तरदायी होगा। मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि यदि वरिष्ठ सहायक उस तारीख के बाद दो साल के भीतर आयोजित उच्च श्रेणी की परीक्षा में सफल हो जाता है, जिस दिन वरिष्ठ सहायक को अस्थायी

रूप से कनिष्ठ सहायक द्वारा हटा दिया गया था, तो कनिष्ठ सहायक को निचली श्रेणी में वापस भेज दिया जाएगा। दो साल के बाद कनिष्ठ सहायक को इस आधार पर वापस नहीं किया जाएगा कि एक वरिष्ठ सहायक ने उच्च श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और वह रिक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था।

यह सिद्धांत कार्यवाहक या अस्थायी रूप से उच्च प्रभाग किरानी में पदोन्नति भविष्य में लागू होंगे ।

4. उच्च प्रभाग में पदोन्नति सुधार पर्ची संख्या 38 द्वारा संशोधित सचिवालय निर्देशों के नियम 2-4 में उल्लिखित सिद्धांतों द्वारा सख्ती से शासित होती रहेगी।”

7. उपरोक्त परिपत्र की कुछ अस्पष्ट शब्दों की सही व्याख्या का प्रश्न पहले 'उमेश चंद्र दास' मामले (उपरोक्त) में पहले आया था। एस. सरवर अली, न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंड पीठ ने इस मामले पर काफी गहराई में विचार किया। दिनेश्वर प्र-साद बनाम बिहार राज्य का मामला (सिविल रिट जर्नल। 1969 का मामला सं. 117), 28 अप्रैल, 1972 में पूर्व खंड पीठ के फैसले का संदर्भ दिया गया था। इसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया:--

“यदि याचिकाकर्ताओं का प्रत्यावर्तन आवश्यक नहीं था तो दिनेश्वर प्रसाद के मामले में निर्णय (उपरोक्त), यह अभिनिर्धारित किया जाना है कि याचिकाकर्ता उन लोगों से वरिष्ठ होंगे जिन्हें बाद में पदोन्नत किया गया था। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता 3 से 11 उत्तरदाताओं से भी वरिष्ठ होंगे। लेकिन, यदि वास्तव में, यू. डी. सहायकों की रिक्तियों की संख्या ऐसी थी कि याचिकाकर्ताओं को वापस करने की आवश्यकता थी और यह गलती से ही था कि याचिकाकर्ताओं को वापस नहीं किया गया था, तो याचिकाकर्ता बाद में पदोन्नत सहायक से वरिष्ठ होने का दावा नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में, यू. डी. सहायकों के रूप में उनका बने रहना नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति के दो साल के भीतर अंतिम लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने

वाले निचली श्रेणी के सहायकों से वरिष्ठ माने जाने के समान अधिकार के साथ उन्हें ऊपरी श्रेणी के सहायकों के रूप में पदोन्नत किया गया। ऐसे मामले में "स्थिति यह होगी कि उन्हें कानूनी रूप से केवल तभी पदोन्नत किया जा सकता है जब रिक्ति या रिक्तियां होती हैं।"

8. अब, ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में, एक ही सवाल दूसरे डिवीजन के सामने त्रिपित नारायण झा (उपरोक्त) के मामले में उठाया गया। इसमें यह लगभग एक उक्ति के रूप में देखा गया था कि यदि कोई निम्न स्तरीय सहायक पहले लेखा में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करता है, तो वह बाद में ऐसा करने वाले सभी लोगों से वास्तव में वरिष्ठ होगा, चाहे उनकी वरिष्ठता कुछ भी हो। अब अभिलिखित बहुत ही संक्षिप्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि वित्त विभाग का परिपत्र, जो निश्चित रूप से इस प्रश्न के निर्धारण के लिए मैग्नाकाटा है, का भी उल्लेख नहीं किया गया था, न ही इसे उद्धृत किया गया था और न ही इसकी बारीकी से व्याख्या की गई थी। पक्षकारों के विद्वान वकील ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य की ओर पीठ का ध्यान आकर्षित नहीं किया कि इस मुद्दे को मुख्य रूप से और वास्तव में पूरी तरह से उक्त परिपत्र के विशेष पैराग्राफ और इसकी सही व्याख्या पर केंद्रित करना था, न कि केवल पक्षकारों के आकस्मिक अभिवचनों पर। फिर से दिनेश्वर प्रसाद के मामले (ऊपर) और उमेश चंद्र दास के मामले (ऊपर) में खंड पीठ के पहले के फैसले, जो पूरी तरह से क्षेत्र को कवर करते थे, का उल्लेख भी नहीं किया गया था विचार करने का प्रश्न तो अलग ही है। माना जाता है, इस मुद्दे को पहली बार स्पष्ट रूप से यह समझ के लिया गया था, कि यह बिन्दु अनिर्णित है। परिणामस्वरूप यह कुछ हद तक संक्षेप में तय किया गया था, कोई तर्क नहीं दिया गया था, न ही कोई सिद्धांत या मिसाल उद्धृत की गई थी। त्रिपित नारायण झा के वाद (ऊपर) में अवलोकन इस प्रकार उमेश चंद्र दास के मामले (ऊपर) में पहले के तर्कपूर्ण विचारों के साथ स्पष्ट रूप से विरोधाभासी है, जो बदले में दिनेश्वर प्रसाद के मामले (ऊपर) में निर्णय पर आधारित था। विद्वान वकील ने त्रिपित नारायण झा के मामले (उपरोक्त) में फैसले

का समर्थन करने का दुःसाहस किया । इसलिए, अत्यंत सम्मान के साथ, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि त्रिपित नारायण झा के मामले में निर्णय जो स्पष्ट रूप से पहले की मिसाल के विपरीत है, सही कानून नहीं है जिसे अब उलट दिया जाता है। उमेश चंद्र दास के मामले (ऊपर) में टिप्पणियों और विचारों की पुष्टि की जाती है।

9. अब एक बार जब उपरोक्त कानूनी मुद्दा सुलझा लिया जाता है, तो हम यहाँ यह भी पाते हैं कि दलीलें और पक्षों का रुख कुछ संक्षिप्त और अस्पष्ट है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, वाद के गुण-दोष को कुछ हद तक अकादमिक बना दिया गया है, क्योंकि जिस प्राथमिक मुद्दे को चुनौती देने की मांग की गई थी, वह था रिट याचिकाकर्ताओं का स्थानांतरण और उन्हें वापस लेना, जिस पर अंतरिम राहत के रूप में रोक लगा दी गई थी। कानून को स्पष्ट करने के बाद, हम, इसलिए, निर्देश देते हैं कि उत्तरदाताओं को उमेश चंद्र दास के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित नियम के अनुसार वरिष्ठता के प्रश्न पर नए सिरे से निर्णय लेना चाहिए।

10. रिट याचिका का निपटारा इन शर्तों के साथ किया जाता है। अर्थ दंड के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

उदय सिन्हा, न्यायमूर्ति

11. मैं सहमत हूँ।

एस. एस. हसन न्यायमूर्ति

12. मैं सहमत हूँ।

खण्डन (डिस्कलेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।